क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 318, मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

शीतकालीन सत्र : कांग्रेस का राज्यसभा और लोकसभा में राफेल पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली एजेंसी। राफेल विमान सौदे पर केन्द्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने राफेल सौदे के मामले में सरकार के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इसी मामले में सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में बताया कि उन्हें कुछ सदस्यों से विशेषाधिकार हनन के नोटिस मिले हैं और वे उनके विचाराधीन हैं।

मामला कोर्ट में विचाराधीनः वेंकैया नायडू

सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर जब सभापति एम वेंकैया नायडू सदस्यों की ओर से दिये विभिन्न नोटिसों और प्रस्तावों की जानकारी दे रहे थे तो आजाद ने कहा कि उन्होंने राफेल सौदे के मामले में देश और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। नायडू ने कहा कि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उन्होंने अभी इस नोटिस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने लोकसभा में दिया नोटिस

जाखड़ ने अपने नोटिस में कहा है कि सरकार के खिलाफ ने राफेल विमान सौदे के बारे में जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट और सदन को गुमराह किया और इसलिए वह सरकार खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस रक्षा सौदे में कीमत पर अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष गलत तथ्य रखे। सुप्रीम कोर्ट ने महालेखा परीक्षक (कैग) की जिस रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार बनाया वह रिपोर्ट अस्तित्व में ही नहीं है तथा संसद की लोक लेखा समिति के साथ साझा नहीं की गयी है। उन्होंने लिखा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्त्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का मामला है। सरकार ने न सिर्फ शीर्ष अदालत को गुमराह किया है, उसने संसद और उसकी लोक लेखा समिति पर भी कलंक लगाया है।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे के बारे में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किये जाने के बाद सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहां कांग्रेस ने सरकार पर इस सौदे के बारे में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है वहीं भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मांग कर रही है कि वे इसके लिए देश से माफी मांगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के राफेल सौदे से संबंधित फैसले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तथा संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के संदर्भ को लेकर मचे बवाल के बाद केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसमें तथ्यात्मक सुधार का अनुरोध किया है।

प्रयागराज में रविवार को ''अक्षयवट'' के दर्शन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

लेह में दर्ज की गई इस मौसम की सबसे ठंडी रात, पारा शून्य से 15.7 डिग्री सेल्सियस नीचे

जम्मू श्रीनगर, एजेंसी। लेह में रविवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से 15.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं, करगिल शहर में तापमान शून्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यह जानकारी मौसम विज्ञान अधिकारियों ने दी। जम्मू में डोडा जिले के भद्रवाह में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं, बटोटे में 1.5 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 3.5 डिग्री सेल्सियस, जम्मू शहर का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस और कटरा आधार शिविर का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हालांकि सुबह के समय धूप निकलने की वजह से जम्मू और अन्य हिस्सों में दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने से लोगों को राहत मिली। कश्मीर के श्रीनगर में रविवार की रात तापमान शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं, काजीगुंड में शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे और निकटतम कोकरनाग में भी तापमान शून्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में तापमान शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे और पहलगाम में शून्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया।

लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में हो सकता है 'महागठबंधन'

नई दिल्ली एजेंसी। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले दिल्ली में 'आप'-कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। दोनों दलों के कई कद्दावर नेता गठबंधन के पक्ष में हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के नेताओं के बीच महागठबंधन (Grand Alliance) को लेकर बात भी हुई है। कुछ 'आप' विधायक भी इस ओर प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे कांग्रेस और 'आप' मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे देश में महागठबंधन की कवायदों के बीच दिल्ली में भी दोनों दलों के कुछ नेता सक्रिय हुए हैं।

महागठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर सूत्रधार कुछ नेताओं का भी मानना है कि भाजपा के खिलाफ दिल्ली में मिलकर लड़ना होगा। तर्क दिया जा रहा है कि बड़े लक्ष्य के लिए आपसी दूरी कम करनी होगी। बीते दिनों विपक्ष की एकजुट बैठक हुई थी। इससे पहले दिल्ली में किसानों के मार्च के मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक मंच पर आए थे। 'आप' नेताओं ने तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत पर हर्ष भी जताया। 'आप' के कुछ विधायकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए।

उधर, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन कई बार गठबंधन के लिए इनकार कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कई बड़े नेता गठबंधन के पक्ष में हैं।

»»»» 1984 सिख विरोधी दंगा :

अरुण जेटली ने कांग्रेस को घेरा तो कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गरमा गई है। दरअसल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सज्जन को अब ताउम्र जेल में रहना होगा। अदालत के फैसले के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपना बचाव कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी घेरा है।

अरुण जेटली ने कांग्रेस को ऐसे घेरा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। जेटली ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस मामले में निर्णय देर में आया लेकिन न्याय मिलना शुरू हो गया है और ये बड़ी बात है। उन लोगों के लिए ये बड़ा फैसला है जो इस नरसंहार के चश्मदीद हैं। ये आजादी के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था जो हमने देखा होगा। जेटली ने इशारों-इशारों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी घेरा। जेटली ने कहा, ये विडम्बना है कि ये फैसला आया उस दिन है जब सिख समाज जिस दूसरे नेता को दोषी मानता है कांग्रेस उसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रही है। जेटली ने कहा, सज्जन कुमार 1984 सिख दंगों के प्रतीक थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने अपने नेताओं को बचाने का पूरा प्रयास किया और वह इसे कवरअप करना चाहती थी।

कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

अरुण जेटली के बयान के थोड़ी ही देर बाद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा, कमलनाथ पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कमलनाथ के सीएम चुने जाने के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा, बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सज्जन कुमार अब किसी पद पर नहीं हैं।

कमलनाथ के विरोध में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा

कमलनाथ के सीएम बनने के विरोध में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने किया विरोध

कमलनाथ को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिये मनोनीत किए जाने के विरोध में दिल्ली भाजपा के एक नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सिख विरोधी दंगों में शामिल थे। बग्गा ने कहा, उन्हें (कमलनाथ को) मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत करने के राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं। वह (कमलनाथ) वही व्यक्ति हैं जो दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि कमलनाथ की जगह किसी और को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। भाजपा के कई नेता बग्गा के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिये मनोनीत कर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है।

विजय गोयल ने लगाया ये आरोप

संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराये जाने के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस पर इस मामले के आरोपी नेताओं को बचाने का आरोप लगया। गोयल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा,1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के नेताओं को जो सजा हुई है उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने न सिर्फ इन दंगों को बढ़ावा दिया बल्कि आरोपियों को बचाने का भी काम किया।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, और क्या दी सजा

बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। करीब 34 साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है।

हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि सज्जन कुमार ताउम्र जेल में रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। यानी सज्जन को 31 दिसंबर से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होगा। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल और तीन अन्य को दोषी बरकरार रखा है।

हरियाणा पहली बार परिवहन विभाग ने स्थायी पोस्ट के लिए महिलाओं को नियुक्त किया

बस कंडक्टर बन महिलाएं तोड़ रहीं बेड़ियां

भतेरी देवी एमए, बीएड कर चुकी हैं, यही नहीं नेट और हरियाणा नेट भी क्वॉलिफाई हैं

जींद (एजेंसी)। टीचर से बस कंडक्टर बनीं 41 साल की भतेरी देवी हरियाणा में पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दे रही हैं। पोस्ट ग्रैजुएट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वॉलिफाई कर चुकीं भतेरी देवी हरियाणा रोडवेज की चुनी हुई 8 महिलाओं में से हैं जिन्हें कंडक्टर बनाया गया है। पहली बार परिवहन विभाग ने कंडक्टर की पर्मानेंट पोस्ट के लिए महिलाओं को नियुक्त किया है।

देवी ने शनिवार को राज रानी, कविका रानी के साथ जींद डिपो पर ड्यूटी जॉइन की। हैबतपुर गांव की रहने वाली देवी एम, बीएड कर चुकी हैं और नेट और हरियाणा नेट भी क्वॉलिफाई कर चुकी हैं। वह टीचर बनन चाहती थीं लेकिन पिछले 10 साल में सरकारी नौकरी न मिलने पर उन्होंने हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के लिए अप्लाई किया। उनके पति की फर्निचर की दुकान है और उनके दो बच्चों हैं। वह बताती हैं कि ऐसा काम करने में जो आमतौर पर पुरुष करते हैं, उन्हें परिवार का पूरा सहारा मिला है।

लड़कियों के लिए प्रेरणा

मोरकी गांव की रहने वाली कविता रानी भी ग्रैजुएट हैं और इस नौकरी में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कविता ने बीकाम फाइल इयर में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया था। वह अपनी पढ़ाई जारी करना चाहती हैं लेकिन इस बात के लिए भी उत्साहित हैं कि वह लड़कियों को जींद जैसे पिछड़े इलाके से आकर यह नौकरी करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हिसार के नरनौंद ब्लॉक से अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे जय भगवान ने कहा कि वह एक महिला कंडक्टर को देखकर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं और समाज को इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। अडिशनल चीफ सेक्रटरी, ट्रांसपोर्ट धनपत सिंह ने कहा कि ये महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा साबित होंगी।

यूपी के गोंडा में युवक बना 'शोले का वीरू', जानिए पूरा मामला

नवाबगंज। गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव में मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी मांगें मंगवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने का तरीका यहां के लोगों ने इजाद किया है। बताते चलें कि पिछले दिनों गांव के पूरे रामप्रसाद मजरे के रंजन नाम का एक दलित युवक कुछ ही दिनों के अंतराल में दो बार टावर पर चढ़कर अपनी भूमि की पैमाइश कराने की जिद करने लगा। दबाव में प्रशासन ने उसकी जमीन की पैमाइश कराते हुए उसे किसी तरह मना कर टावर से नीचे उतारा।

मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में कमलनाथ, कर्ज माफी वाली फाइल पर किए साइन

शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोउल्लस के साथ जमकर नारे लगाये। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित संप्रग के कई दिग्गज नेता मौजूद थे।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कमलनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी।

बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था। इससे पहले सोमवार दोपहर को कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने सोमवार दोपहर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शहर के जम्बूरी मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ दिलाई।

कमलनाथ ने हिन्दी में शपथ ली और अकेले शपथ ग्रहण किया। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी।

शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच पर आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोउल्लस के साथ जमकर नारे लगाये। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित संप्रग के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, द्रमुक नेता एम के स्टालिन, तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी शामिल हैं। कार्यक्रम में बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी आना था लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों नहीं आ सके।

संपादकीय

राफेल सौदे

फेल सौदे पर कांग्रेस की रणनीति को देखें तो उसकी अति आक्रामकता समझ में आती है। राफेल पर राहुल गांधी जितने आरोप लगा चुके हैं और जैसे तीखे शब्द प्रयोग करते रहे हैं, उसके बाद पार्टी के चुप हो जाने से पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। किंतु अगर सर्वोच्च अदालत ने राफेल सौदे पर एक फैसला दे दिया, उसे इसमें ऐसा कोई संदेहास्पद पहलू नजर नहीं आया, जिसके आधार पर जांच की अनुमति दी जाए तो फिर इसके बाद कांग्रेस जितना कुछ कर ले इस सौदे को आम लोगों की नजर में संदेहों के घेरे में नहीं ला सकती। आखिर लोग यह तो प्रश्न उठाएंगे न कि सुप्रीम कोर्ट सही या कांग्रेस? इसमें ज्यादातर लोग किसे सही मानेंगे यह बताने की आवश्यकता नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और लोक लेखा समिति (पीएसी) से संबंधित एक पंक्ति को आधार बनाकर कांग्रेस भले यह प्रचारित करे कि सरकार ने झूठा शपथपत्र दिया, पर अब सरकार स्वयं न्यायालय जा चुकी है। यह पंक्ति टाइपिंग की भूल लगती है, जिसमें संशोधन हो सकता है। कैग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसे आने वाले समय लोक लेखा समिति को दिया जाएगा। उसके बाद यह संसद के पटल पर आएगा। न्यायालय ने इस पहलू को अपने फैसले का आधार बताया भी नहीं है। उसने शेष सारी बातें कही है कि सौदे में उसे क्यों कुछ धुंधला नजर नहीं आया और उसी संदर्भ में कोष्ठक में कैग और पीएसी की बात लिखी है। कांग्रेस और विरोधियों को राजनीति करनी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय के किसी फैसले की इस तरह छीछालेदर देश को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर कोई न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट है तो वह बड़ी पीठ में इसे ले जा सकता है। वहां के बाद संविधान पीठ और अंततः पुनर्विचार याचिका का पड़ाव है। लोकतांत्रिक व्यवहार का तकाजा यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अपनी भूल स्वीकार करें। उनका कहना चाहिए था कि हमें पहले इसमें भ्रष्टाचार दिखा, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सौदे को जांच के लायक नहीं माना तो हम न्यायालय का सम्मान करते हुए अपना अभियान बंद कर रहे हैं। पार्टियां चुनावी राजनीति करें, लेकिन भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़े इस तरह के सौदों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बाहर रखें। चिंता का विषय यही है कि ऐसा हो नहीं रहा।

हिंसा पर उतारू भीड

कश्मीर घाटी में हिंसा पर उतारू भीड़ पर सेना की कार्रवाई में सात प्रदर्शनकारियों की मौत और 30 के आसपास घायल होने की घटना पर भारी उबाल है। यह जाने-समझे बिना कि पत्थरबाज किसके हमदर्द हैं और किसके दुश्मन, नेता गुमराह युवाओं को भरमाने में जुट गए हैं। इन सातों प्रशर्दशनकारियों पर सेना को अंतिम वार इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराने के बाद पत्थरबाजों की टोली सेना पर टूट पड़ी। घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले की है। हालांकि कमोबेश यह सूरत दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में है। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि घाटी में पत्थरबाजी केवल एक धंधा ही नहीं, आतंकवादियों के बचाव का जरिया भी बन चुकी है। इस तय से अच्छी तरह परिचित होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हर वक्त उनके पक्ष में खड़ी नजर आई। और यहां तक कि उनके खिलाफ नरमी बरतने की खुली पैरवी करतीं रहीं। इसी साल जनवरी में करीब 4000 पत्थरबाजों से मुकदमे वापस सिर्फ महबूबा की पहल पर लिये गए। जबकि सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवान कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने फर्ज को अंजाम देते हैं, यह जगजाहिर है। उल्टे पत्थरबाजी की घटना में हर साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मी जख्मी होते हैं। अभी अक्टूबर माह में ही सड़क की सुरक्षा में लगे जवान की पत्थरबाजी में मौत हो गई। क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? आखिर क्यों अपने ही देश के जवानों पर कोई पत्थर बरसाएगा और सेना उसे सहेगी? पहले भी कई बार सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने पत्थरबाजों के खिलाफसख्ती की बात कही थी। उन्होंने साफतौर पर कहा था कि आतंकवादियों की मदद करने वाले पत्थरबाजों को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, जिस तरह से आतंकवादियों को किया जाता है। साफ है कि पत्थरबाज आतंकवादियों के सुरक्षा ढाल बनते हैं। उनकी मंशा सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को पटरी से उतारना होता है। कई बार वो सफल भी होते हैं। मगर ताजा घटना से हो सकता है उनकी सोच पर असर पड़े और वह सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाने के बजाय सूबे में अमन बहाली को लेकर सकारात्मक समझ के साथ कदमताल करें। दुख इस बात का है कि मुख्यधारा से कटे और देश विरोधी हरकत में शामिल युवाओं को समझाने के बजाय नेता उनका पक्ष लेते हैं।

कार्यपालिका और न्यायपालिका

अदालत चार याचिकाकर्ताओं की याचिका पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की अनुमति प्रदान कर देती तो हमारे लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ (कार्यपालिका और न्यायपालिका) न केवल एक दूसरे के सामने आ खड़े होते, बल्कि तमाम भावी सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसी कार्यवाहियों का बीजारोपण हो गया होता। कैसे? सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे पर अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देता तो देश की रक्षा तैयारियों को झटका लगता। इसी पहलू पर अदालत ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। फैसले में इस बात का उल्लेख भी किया है। फिर, भावी सरकारों के लिए भी इसके दीर्घकालिक असर होते।

सतीश पेडणोकर

14 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल मामले में दिए गए फैसले पर दो पहलुओं के मद्देनजर गौर किया जाना जरूरी है। पहला, देश के समूचे राजनीतिक परिदृश्य के लिए इसके क्या फलितार्थ हैं; और दूसरा, क्या फैसले के उपरांत मोदी सरकार का आखिरकार राफेल के भूत से पिंड छूट जाएगा। सबसे पहले प्रथम पहलू को देखते हैं : फैसला मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत है। निश्चित ही विपक्ष को सदमा लगा है। लेकिन तय है कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से बेहद संवेदनशील मसले पर फैसला चाहा था। अदालत चार याचिकाकर्ताओं की याचिका पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की अनुमति प्रदान कर देती तो हमारे लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ (कार्यपालिका और न्यायपालिका) न केवल एक दूसरे के सामने आ खड़े होते, बल्कि तमाम भावी सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसी कार्यवाहियों का बीजारोपण हो गया होता। कैसे? सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे पर अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देता तो देश की रक्षा तैयारियों को झटका लगता। इसी पहलू पर अदालत ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया।

फैसले में इस बात का उल्लेख भी किया है। फिर, भावी सरकारों के लिए भी इसके दीर्घकालिक असर होते। भविष्य में कोई सरकार किसी देश या विदेशी कंपनी के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा या कोई प्रमुख नीतिगत फैसला करती तो विपक्ष राफेल फैसले (फैसला याचिकाकर्ताओं के मनमाफिक आता तो) को नजीर के रूप में पेश करते हुए सरकार के फैसले को रुकवाने की कोशिश करता। यह स्थिति किसी आपदा से कम न होती। सरकार के लिए कामकाज चलाना असंभव हो जाता। ध्यान रखना होगा कि अदालतें कार्यपालिका के क्षेत्र में इस तरह प्रवेश करने और वायु सेना के लिए खरीदे जाने वाले विमानों की कीमत जैसे मुद्दों पर फैसला देने लगीं तो सरकार के होने का क्या मतलब रह जाता है? ऐसे में तो अदालतों को ही देश चलाना चाहिए और देश चलाने के लिए सरकार चुनने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जरूरी है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद अपनी हद में रहें। एक दूसरे की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण न करें। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का राफेल मामले में दिया गया फैसला सराहनीय है।

अब देखते हैं दूसरे पहलू की तरफ। पहलू यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के विरोधियों को निपटाने वाला है, क्या राफेल का भूत सदा के लिए दफन हो गया है? नरेन्द्र मोदी सरकार को राफेल मामले पर फैसले को लेकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भाजपा को बोफोर्स मामले को नहीं भूलना चाहिए जब उसने कांग्रेस हाई कमान को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उन दिनों कांग्रेस की सरकारों को हर दफा लगा कि बोफोर्स का जिन्न बोतलबंद हो गया है, लेकिन स्वीडन से ऐसा कुछ आता कि राजनीतिक गरमा जाती। कांग्रेस की सरकारों के लिए फिर फिर कर समस्याएं उभर आतीं। उसी प्रकार राफेल मामला भी बड़े ही संजीदा चरण में पहुंच गया है। फ्रांस के फ्रेंच नेशनल प्रॉसिक्यूशन ऑफिस में आंतरिक जांच की कार्यवाही चल रही है। आने वाले दिनों में फ्रांस की तरफ से कुछ विस्फोट जैसा होने पर हैरत में नहीं पड़िएगा। फ्रांस की इस आंतरिक जांच में किसी तरह की अनियमितताएं सामने आई तो यकीनन मोदी सरकार की जान सांसत में पड़ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत बेमानी हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तय-जो कहा नहीं गया है-पर विचार करते हैं। फैसले में यह नहीं कहा गया है कि राफेल सौदे में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्योंकि यह मुद्दा शीर्ष अदालत के सामने विचार के लिए था ही नहीं। याचिकाओं में अपील की गईथी कि अदालत द्वारा गठित विशेष जांच टीम द्वारा अदालत की निगरानी में राफेल मामले की जांच के लिए अदालत अपनी व्यवस्था दे। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार ने न केवल 36 राफेल विमानों के लिए कीमत से ज्यादा का भुगतान किया, बल्कि मिलीभगत के पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) को भी बढ़ावा दिया। अदालत द्वारा सरकार को दी गई क्लीन चिट केवल तीन पहलुओं तक सीमित है:

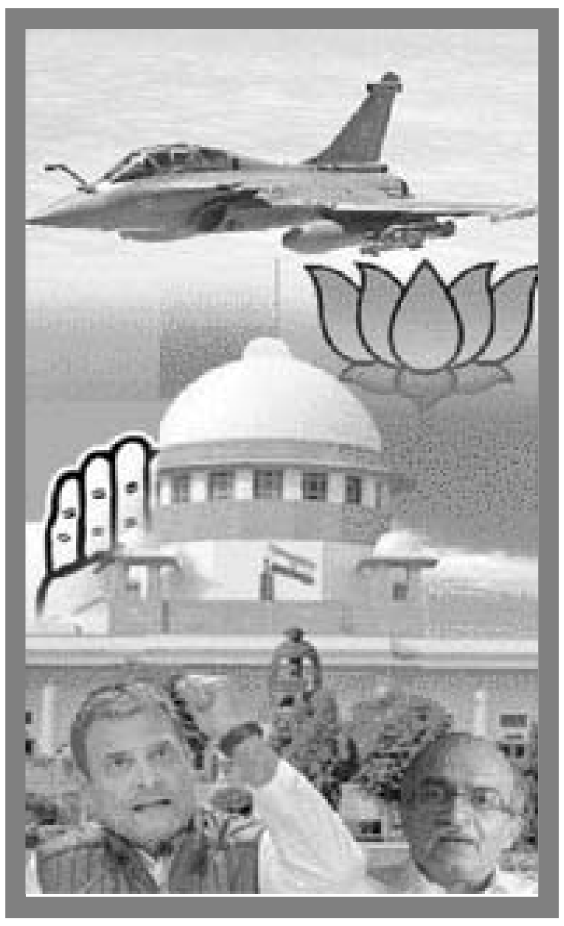

मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 126 की बजाय 36 राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया; राफेल विमानों की कीमत प्रतिक्रया; तथा दसॉल्ट द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस समेत इंडियन ऑफसेट पार्टनर तय किया जाना। इन्हें लेकर अदालत ने कहा :सौदे में निर्णय-प्रक्रिया पर संदेह की गुंजाइश नहीं है। जरूरी है कि देश में चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान लाए जाएं। विमानों की जरूरत और गुणवत्ता पर संदेह न होने की सूरत में कीमतों की तुलनात्मक जानकारियों पर गौर करना अदालत का काम नहीं है। खरीद, कीमत और ऑफसेट पार्टनर के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। सौदे में व्यावसायिक पक्षपात का प्रमाण नहीं मिलता। दसॉल्ट द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चयन में कुछ गलत नहीं दिखता। राफेल सौदे पर सवाल उस समय उठे जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्कोस हॉलें का बयान आया। इस बयान को न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती कि उसे 36 विमान लड़ाकू खरीदने चाहिए या 126 लड़ाकू विमान। इस फैसले का एक हिस्सा और है, जो यकीनन भाजपा नेताओं और मंत्रियों के कानों में अमृत घोलने सरीखा है। कीमत प्रक्रिया को लेकर अदालत का कहना कि कीमतों को लेकर तुलनात्मक जानकारियों पर गौर करना अदालत का काम नहीं है। भाजपा नेता इस बात से भी खुश होंगे कि अदालत ने कहा है कि विमानों की जरूरत और गुणवत्ता संदेह से परे हैं। तो अब आगे क्या हो? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन यही आखिरी शब्द नहीं है। इस मामले के याचिकाकर्ता-यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण-जूझारू और अनुभवी हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फैसले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में पुन:समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। बहरहाल, हिन्दी पट्टी के तीन प्रमुख राज्यों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़-के असेंबली चुनावों में जीत से सातवें आसमान पर पहुंची कांग्रेस राफेल मामले को गरमाए रखना चाहती है। चाहती है कि पांच महीनों बाद होने वाले लोक सभा चुनाव तक यह मुद्दा बना रहे।

चलते चलते

राजनैतिक अथो

तेलंगाना और मिजोरम में सुप्रीमो संस्कृति के तहत दल का अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बना। मगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक से ज्यादा दावेदार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की घोषणा के साथ ही पांच राज्यों में हुए चुनाव राजनैतिक अर्थो में संपन्न हो गए। तेलंगाना और मिजोरम में सुप्रीमो संस्कृति के तहत दल का अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बना। मगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक से ज्यादा दावेदार होने से कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में युवा नेतृत्व को कमान सौंपे जाने की कयासबाजी जोरों पर थी। मध्य प्रदेश में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा थी, वहीं राजस्थान में सचिन पायलट की। मगर दोनों राज्यों में ''अनुभव' को तरजीह दी गई। जहां सिंधिया को मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति की बागडोर दी गई थी, वहीं पायलट को राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की। दोनों प्रदेशों में इसे प्रदेश के युवाओं को अपने पाले में लाने के संदेश के तौर पर देखा गया। कुछ हद तक चुनाव परिणामों में इसकी झलक भी मिली। मगर इन दोनों का अपने-अपने राज्यों के प्रमुख के तौर चयन ना होने से एक तबका मायूस भी हुआ। कौन बना, क्यों बना-कौन नहीं बना, क्यों नहीं बना; की मगजमारी का दौर राजनीतिक पंडितों द्वारा जारी है। मगर पिछले साल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अपनी ताजपोशी के बाद राहुल गांधी से यह उम्मीद की जा रही थी, कि वह देश की सबसे पुरानी पार्टी में युवाओं को अच्छी संख्या में तरजीह देंगे। हालांकि संगठन में उन्होंने इस फार्मूले पर अमल भी किया, मगर जब राज्यों में कमान सौंपने की बारी आई तो वह हौसला (वैसे दोनों दावेदारों की राजनीतिक जड़ों को भी कारण माना जा रहा है, वंशवाद पर बहस जोर पकड़ सकती थी) नहीं दिखा पाए। आज जब देश की 65 फीसद आबादी 35 साल से कम उम्र की है, दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए 65 पार लोगों का चुनाव कहीं से 2019 के लिए अच्छा संदेश नहीं कहा जाएगा। चुनाव से यही संदेश गया कि पार्टी पर आज भी ''ओल्ड गॉर्ड' हावी है। वहीं 32 फीसद आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ में भी 57 साल के भूपेश बघेल का चयन उदाहरण के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अजित जोगी के आदिवासी होने ना होने के विवाद को अलग कर दें तो आज तक राज्य में कोई आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भले ही कांग्रेस ने हिन्दी पट्टी के इन तीन राज्यों में फतह हासिल कर ली, मगर मुख्यमंत्रियों का चुनाव उन्हें बदलाव के वाहक के तौर पर सामने नहीं लाता।

फोटोग्राफी...

कोलकाता में रविवार को आयोजित टाटा स्टील दौड़ प्रतियोगिता में विजय दिवस ट्रॉफी के लिए भाग लेते अलग-अलग आर्मी टीम के अभ्यर्थी।

''संतुलित और समावेशी'

राज्यों में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों से निकला परिणाम यह संकेत दे रहा है कि जनता राजनीतिक स्तर पर मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच विभाजित है और आगामी लोकसभा चुनाव भी इन दो पार्टियों के बीच ही होना संभावित है। अन्य दलों का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। उनमें से कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। बसपा की घोषित रूप से गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा की कोई नीति नहीं रही है। उसका उद्देश्य रहा है अपने दम पर सत्ता पर काबिज होना। ऐसी सम्भावना नहीं होने पर वह किसी अभी अन्य पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार नहीं, अपितु बसपा की मदद से बनाने वाली मजबूर सरकार की पक्षधर है। वैसे राजनीति में किसी नीति या सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं होता है। अवसर आने पर, नीति और सिद्धांत तो ताक पर रखकर किसी भी राजनीतिक दल या मोर्चा के साथ तालमेल कर सरकार बनाई जा सकती है। यहां तक कि विरोधी विचारधारा वाले दल या मोर्चा के साथ मिलकर भी। राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन बनाना और तोड़ना आज की राजनीति में सामान्य घटना है। इसका अनुकरण कर बसपा ने भी कई बार सरकार बनाई है। लेकिन बसपा और अन्य पार्टियों में एक मौलिक अंतर है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां किसी-न-किसी रूप में, कम या ज्यादा हिन्दुत्व का पोषण करती हैं और इस रूप में वे वर्ण-व्यवस्था और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त भारतीय समाज-व्यवस्था के ताने-बाने को थोड़ी-बहुत लीपापोती के साथ यथावत बनाए रखती हैं। इनमें किसी पार्टी का हिन्दुत्व कट्टर और किसी का उदार हो सकता है। हिन्दुत्व का ही दूसरा नाम ब्राह्मणवाद है। बसपा की पहचान एक अंबेडकरवादी पार्टी के रूप में है और अंबेडकरवाद की दृष्टि में ब्राह्मणवाद दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाजपा के साथ गठजोड़ के दौरान जहां बसपा ने बहुजन से सर्वजनवाद की ओर कदम बढ़ाए, ब्राह्मणवाद ने बसपा की विचारधारा में सेंध लगा दी। आज बसपा न उत्तर प्रदेश में सत्ता में और है और न संसद उसका कोई वजूद है। पिछले कुछ उपचुनावों में उसने भाजपा के विरु द्ध सपा का समर्थन कर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की, किंतु हाल के विधानसभा चुनावों में जिस तरह उसने छत्तीसगढ़ में गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस की नीति को अपनाते हुए अजित जोगी के साथ गठबंधन कर और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपने दम पर चुनाव लड़ा, उससे लगता नहीं कि कोई बड़ा लाभ उसको हुआ है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी उसकी स्थिति बहुत सशक्त नहीं है। गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा की नीति अपनाकर अपने बूते चुनाव लड़ना बसपा की राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। वह भी उन राज्यों में जहां बसपा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। एक ओर चुनाव बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना, दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा विरोधी मोर्चा की बैठकों से दूर रहना बसपा के द्वंद्व को दर्शाता है। बसपा की यह एक बड़ी कमजोरी रही है कि उसने अपना कोई थिंक टैंक विकसित नहीं किया। बसपा की दूसरी कमजोरी अपने पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना भी रहा है। कई सवालों और सकटों से घिरी बसपा के लिए यह आत्ममंथन का समय है। लोक सभा चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है। बसपा को अभी से यह तय करना होगा कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपनी किस प्रकार की छवि के साथ जनता के बीच जाना है।

सत्संग

''वसुधैव कुटुम्बकम'

धर्मतंत्र का तीसरा कार्य जो करने का है, जिससे कि मनुष्य की अन्त:चेतना विकसित होती हो, वो है ''सामाजिक क्रांति'। समाज की छुट-पुट बुराइयां जो दिखाई पड़ती हैं, इनको दूर करने के लिए विरोध और आंदोलन करने की तो जरूरत है ही, लेकिन श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए जिन रचनात्मक वस्तुओं को जीवन में धारण करने की जरूरत है, वो उच्चस्तरीय सिद्धांत हैं, जो व्यक्ति को समाजपरक बनाते हैं। ''आत्मवत सर्व्भूतेषु' की मान्यता जन-जन के अंत:करण में जगाई जानी चाहिए। हरेक के मन में ये विास होना चाहिए कि जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वही हमें दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक क्रांति के लिए ये सिद्धांत आवश्यक है कि हर आदमी के मन में गहराई तक प्रवेश कर जाए। हममें से हर आदमी के मन में एक विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए कि ''वसुधैव कुटुम्बकम' ''सारा विश्व ही हमारा कुटुम्ब है'। दो-पांच आदमी नहीं, बल्कि सारी वसुधा ही हमारा कुटुम्ब है और जिस तरीके से अपने घर का और बाल-बच्चों का हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही विश्व में सुख और शांति के लिए ध्यान रखना और प्रयत्न करना जरूरी है। सामाजिक क्रांति के लिए उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिवाद के ऊपर अंकुश करके समाजपरक बनता चला जाए। ''आत्मन: प्रतिकूलानि परेषाम न: समाचरेत' का सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो सामाजिक जीवन में श्रेष्ठता का आ जाना स्वाभाविक है। मिल-बांट कर खाने की वृत्ति अगर हमारे भीतर हो, तो जो हम सबके पास है, उसी से सबका गुजारा बड़े मजे से हो सकता है। हम उदारता से उपार्जन करें। उपार्जन का उपयोग करना सीखें, उपभोग नहीं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहिए और सहकारिता के सिद्धांतों को अपनाकर पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में हर काम की व्यवस्था बनानी चाहिए। भगवान का अवतार जहां कहीं भी होता है, वहां ये मान्यता निश्चित रूप से रहती है कि भगवान के अवतार जितने भी हुए हैं, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए, हमारे भीतर भगवान की प्रेरणा आए तो दोनों ही क्रियाकलाप हमको समान रूप से अपनाने पड़ेंगे।

कनाडा सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति रद्द करने पर कर रहा है विचार: ट्रूडो

मांट्रियल (एजेंसी)।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को कहा कि उनका देश सऊदी अरब के साथ 2014 के एक बड़े हथियार सौदे को रद्द करने के तौर तरीकों पर विचार कर रहा है। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी अरब की भूमिका सामने आने और यमन में रियाद की अगुवाई में लड़ाई के बीच ट्रूडो इस सौदे को नहीं तोड़ने को लेकर विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं।

ट्रूडो ने इससे पहले कहा था कि पिछले कंजरवेटिव प्रशासन द्वारा किये गये इस सौदे से 'कनाडाइयों द्वारा बिना बहुत बड़ा हर्जाना दिये' हाथ खींचना 'बिल्कुल कठिन है।' लेकिन खशोगी की हत्या में सऊदी अरब के सीधा हाथ होने का सबूत सामने आने के बाद कनाडा ने नवंबर में इस हत्या से जुड़े 17 सऊदी नागरिकों के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा की थी। दो अक्टूबर को खशोगी की हत्या कर दी गयी थी। ट्रूडो ने एक साक्षात्कार में कहा, ''एक पत्रकार की हत्या बिल्कुल अस्वीकार्य है और यही वजह है कि कनाडा शुरू से उस पर जवाब और हल की मांग कर रहा है।''

उन्होंने कहा, ''सऊदी अरब को बख्तरबंद हल्के वाहन निर्यात करने के लिए (पूर्व प्रधानमंत्री) स्टीफन हार्पर द्वारा किये गये 15 अरब के डॉलर का सौदा वाकई हमें हिरासत में मिला है।'' उन्होंने कहा, ''यह देखने के लिए हम निर्यात परमिट पर चीजें खंगाल रहे हैं कि सऊदी अरब को इन वाहनों का निर्यात रोकने का का क्या कोई तरीका है।''

ट्रूडो ने अक्टूबर को सीबीसी रेडियो के साथ साक्षात्कार में कहा था कि इस सौदे को तोड़ने का जुर्माना एक अरब कनाडाई डालर से अधिक हो सकता है। इस सौदे को रद्द करने में विफल रहने पर विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता ट्रूडो की आलोचना कर रहे हैं।

अमेरिका के साथ् श्व में एक और बैठक करेगा तालिबान

इस्लामाबाद। तालिबान ने अमेरिका के साथ 'एक और' बैठक करने की बात कही है जो इस बार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगी और इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने विस्तृत ब्यौरा न देते हुए एक संक्षिप्त बयान में कहा कि यह बैठक सोमवार को होगी। विदेश मंत्रालय ने पहले ऐसी बैठकें होने से न तो इनकार किया है और न ही उनकी पुष्टि की लेकिन अमेरिकी विशेष शांति दूत जालमे खलीलजाद ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने 17 साल चले इस संघर्ष में शामिल सभी अफगानों से मुलाकात की। सितंबर में खलीलजाद की नियुक्ति इसी लक्ष्य से की गई थी कि इससे शांति वार्ता को तेजी मिलेगी और अब इसने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान ने इससे पहले कहा था कि वह बातचीत के ताजा चरण की योजना बनाने में मदद करेगा। इन वार्ताओं का मकसद काफी लंबे अरसे से जारी इस संघर्ष में अमेरिका की प्रतिभागिता को खत्म करना है जिसके चलते उसे लगभग एक ट्रिलियन डॉलर कीमत चुकानी पड़ी है।

सार समाचार

बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने 'दासता कानून' के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

बुडापेस्ट। हंगरी सरकार द्वारा हाल ही में पारित एक नए ''दासता कानून'' के खिलाफ हजारों लोगों ने रविवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ग्रेनेड फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन लोगों पर आँसू गैस के गोले छोड़े। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सरकार ने नए को पारित किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 15,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। वर्ष 2010 में ओरबान के सत्ता में लौटने के बाद से देश में पहली बार रैली हुई है। यूनियनों और विपक्षी दलों ने इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इस कानून के मुताबिक, सालाना काम के घंटों में वृद्धि की गई है, जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ 250 से 400 घंटे तक अतिरिक्त काम करा सकता है और कर्मचारियों को भुगतान करने में तीन साल तक की देरी कर सकता है। इस पर सरकार का कहना है कि श्रमशक्ति की कमी से जूझ रहे नियोक्ताओं और कंपनियों को इसकी जरूरत है तथा इससे उन लोगों को लाभ होगा जो अतिरिक्त समय तक काम कर वेतन से अधिक धन कमाना चाहते हैं।

जापान के रेस्तरां में हुए भीषण धमाके में 42 लोग घायल

तोक्यो। उत्तरी जापान के एक रेस्तरां में हुए भीषण धमाके में 42 लोग घायल हो गए। विस्फोट से निकटवर्ती इमारतें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे कुछ निवासियों को आश्रयगृह में पनाह लेनी पड़ी। रविवार रात साप्पोरो में धमाके के बाद आग लग गई जिससे आस-पास स्थित इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं। पुलिस ने बताया कि धमाके के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। समाचार एजेंसी 'जीजी' ने बताया कि एक व्यक्ति का मुंह बुरी तरह झुलस गया लेकिन किसी भी घायल की जान को कोई खतरा नहीं है। विस्फोट में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। साप्पोरो के दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रेस्तरां की दो मंजिला लकड़ी की इमारत, एक रियल एस्टेट एजेंसी और एक क्लिनिक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारी ने कहा, ''हम मौके पर मौजूद पुलिस के साथ नुकसान का पता लगा रहे हैं।''

फिलीपींस की सुंदरी के सिर सजा ताज, भारत की नेहल चुडासमा खिताब की दौड़ से बाहर

नई दिल्ली। फिलीपींस की कैटरिओना ग्रे के सिर पर मिस यूनीवर्स 2018 का ताज सजा. प्रतियोगिता में दक्षिण अफीका की प्रतियोगी फर्स्ट रनर-अप और वेनेजुएला की सेकंड रनर अप रही. भारत की नेहल चुदासमा शीर्ष 20 तक भी नहीं पहुंच पाईं. लाल रंग के हाई स्लिट गाउन में मिस यूनीवर्स का ताज सिर पर पहने ग्रे काफी उत्साहित नजर आईं. मिस यूनिवर्स 2018 प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं भारत की नेहल चुडासमा शीर्ष 20 से बाहर हो गई हैं. मुंबई की रहने वाली 22 साल की नेहल 67नें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 94 प्रतिभागियों में से शामिल थीं. शीर्ष 20 में आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोस्टा रिका, कुराको, ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, जमैका, नेपाल, फिलीपींस, पोलैंड, प्यूटरे रिको, दक्षिण अफीका, थाईलैंड, अमेरिका, वेनेजुएला और वियतनाम की सुंदरियां शामिल रहीं. इस शो का आयोजन पांच बार एमी अवॉर्ड जीत चुके स्टीव हार्वी कर रहे हैं.

सीमा पर रूस की बढ़ी हुई सैन्य मौजूदगी अब भी बरकरार: यूक्रेन नेता

कीव (एजेंसी)।

यूक्रेन और रूस के बीच नवंबर से तनाव बढ़ने के बाद से यूक्रेन की सीमा पर बढ़ी हुई सैन्य मौजूदगी को बरकरार रखते हुए रूस ने अब तक अपने बलों के '10 प्रतिशत से भी कम सैनिकों' को वहां से हटाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'सबसे बड़ा हिस्सा (सैन्य दलों का) अभी भी वहां है, 10 प्रतिशत से भी कम को वापस बुलाया गया।' पोरोशेंको ने नवंबर के आखिर में काला सागर में रूस के साथ समुद्री संघर्ष के बाद से रूस के सीमा पर तेजी से सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का आरोप लगाया था जिसकी प्रतिक्रिया में यूक्रेन ने 'बड़े युद्ध' की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में कीव ने रूस की सीमा से लगने वाले 10 क्षेत्रों में 30 दिन के लिए मार्शल कानून लगा दिया था जिसके बाद से दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया। पोरोशेंको ने कहा, 'यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य बलों की घुसपैठ का खतरा अब भी मौजूद है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए।' साथ ही पोरोशेंको ने कहा कि उन्हें मार्शल कानून हटाए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता। रूस ने 25 नवंबर को यूक्रेन के तीन नौसैन्य पोतों को जब्त कर चालक दल के 24 सदस्यों को हिरासत में ले लिया था।

घाना विश्वविद्यालय से गांधी जी की प्रतिमा हटाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका ने जताया विरोध

जोहानिसबर्ग (एजेंसी)।

महात्मा गांधी की पौत्री की अगुवाई वाले समूह समेत दक्षिण अफ्रीका के कई गांधीवादी समूहों ने घाना के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से वैश्विक शांति के प्रतीक की प्रतिमा को हटाने की निंदा की. इन समूहों ने गांधीजी के खिलाफ नस्लवाद के आरोपों पर भी कड़ा ऐतराज जताया. गांधीजी पर अश्वेत अफ्रीकियों के खिलाफ नस्लवादी होने का आरोप लगाने की शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय से प्रतिमा को हटाया गया था.

भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में दोनों देशों के बीच रिश्तों के प्रतीक के तौर पर अकरा में घाना विश्वविद्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन लेक्चरर एवं छात्र कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को हटाने की मुहिम शुरू कर दी. इसके लिए उन्होंने गांधीजी द्वारा लिखित कुछ अंशों का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय, अश्वेत अफ्रीकियों से 'बहुत ज्यादा श्रेष्ठ' थे.

प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेकते हुए, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस हफ्ते के शुरू में आखिरकार प्रतिमा को हटा दिया. डरबन में गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट चलाने वाली गांधीजी की पोती इला गांधी ने कहा कि वह घाना में हुए घटनाक्रम से दुखी हैं.'' 'संडे ट्रिब्यून' ने इला गांधी के हवाले से कहा, '' मुझे लगता है कि बयानों को बिना विश्वसनीयता दिए एक या दो बयानों के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में यह सोच पैदा करने वाला बयान है जिसने नस्लवाद को नकारा. यह खासतौर पर परेशान करने वाला है क्योंकि गांधीजी जिंदगी भर लोगों को बांटे जाने के खिलाफ लड़े.''

पाकिस्तान ने भारतीय कैदी हामिद अंसारी को रिहा किया, आज भारत आएगा

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को रिहा किया कर दिया है। वह मंगलवार को भारत आएगा। उसे तीन साल की सजा हुई थी। उसको सजा की अवधि शनिवार को खत्म हुई थी। वह पाकिस्तान की कोहाट सेंट्रल जेल में बंद था। यह जानकारी पाकिस्तान विदेश विभाग ने दी है।

मुंबई के रहने वाले हामिद निहाल अंसारी (33) कोहाट सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के आरोप में 15 दिसंबर 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने पर 2012 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे, जिससे उनकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। यह फर्जी पहचान पत्र उन्हें इस फेसबुक फ्रेंड ने भेजी थी।

हामिद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और खुद को बेकसूर बताया था। इस साल अगस्त में कोर्ट ने सजा में छूट की मांग कर रही हामिद की याचिका तब खारिज कर दी थी, जब आंतरिक मंत्रालय ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उन्हें 15 दिसंबर को रिहा कर दिया जाएगा।

अमेरिका में पाकिस्तानियों ने की बैठक, आतंकियों को मिलने वाली मदद को रोकने का किया ऐलान

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

असंतुष्ट पाकिस्तानियों के एक समूह ने वहां की सरकार से ऐसे आतंकवादी समूहों के 'वित्तपोषण एवं सहयोग' को रोकने का आह्वान किया है जो देश में खुले तौर पर काम कर रहे हैं. इनमें मुंबई आतंकवादी हमले के सरगना हाफिज सईद नीत जमात-उद-दावा का नाम भी शामिल है.

असंतुष्ट सदस्यों ने विचार-विमर्श के लिए यहां तीन दिवसीय एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और बढ़ती तानाशाही, लोक नीतियों पर सेना के बढ़ते नियंत्रण और असैनिक संस्थानों को कमजोर किए जाने को लेकर चिंता जाहिर की.

अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व दूत हुसैन हक्कानी ने सम्मेलन के समापन के दिन रविवार को कहा, 'पाकिस्तान के लोग हमेशा सुखी रहें और उन्हें उस तानाशाही के बुरे सपने से निकलने का रास्ता मिल सके जो हमारे देश को लगातार श्रापित कर रहा है.'

'आतंकवाद के खिलाफ और मानवाधिकारों के साथ दक्षिण एशियाई' (साथ) बैनर तले और हक्कानी एवं अमेरिकी स्तंभ लेखक मोहम्मद ताकी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागियों ने एक प्रस्ताव में कहा कि पाकिस्तान में 2018 के चुनावों के नतीजों में विश्वसनीयता का अभाव है और इन्हें राजनीतिक दृष्टि से अत्याधिक योजनाबद्ध चुनावों में से एक की तरह देखा गया.

प्रस्ताव में कहा गया, 'चुनावों ने पीटीआई समर्थकों के बीच एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीदें जगा दी थीं लेकिन अनुमान के उलट नयी सरकार के पहले तीन महीनों में उन उम्मीदों को झटका लग गया.'

पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहे आतंकवादी समूहों के 'वित्तपोषण एवं सहयोग' को रोकने की सरकार से अपील करते हुए प्रतिभागियों ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान (टीएलपी), जमात उद दावा (जेयूडी), लश्कर-ए-झांग्व (एलईजे) समेत अन्य घृणा समूहों और चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

बोन मैरो कैंसर अब नहीं रहेगा लाइलाज, दिखी उम्मीद की नई किरण

लंदन (एजेंसी)।

गंभीर बोन मैरो कैंसर के इलाज की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। ब्रिटेन की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने क्लीनिकल ट्रायल में एक दवा को मायलोमा के मरीजों पर प्रभावी पाया है। इस कैंसर से जूझ रहे मरीजों को लेनालिडोमाइड दवा दी गई। लैंसेट ओंकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित नतीजों के मुताबिक, जिन मरीजों को यह दवा दी गई, उनमें अन्य के मुकाबले ज्यादा सुधार देखा गया।

मायलोमा प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर है जो रीढ़, सिर, पेल्विस और पसलियों में होता है। यह गंभीर किस्म का कैंसर है। इसके इलाज में प्राय÷ कीमोथेरेपी और स्टेम-सेल प्रत्यारोपण की पद्धति अपनाई जाती है। प्रोफेसर ग्राहम जैकसन ने कहा, 'हमारे शोध से यह सामने आया है कि ऐसे मरीज जिनमें हाल ही में इस कैंसर की पहचान हुई हो, उन्हें स्टेम- सेल प्रत्यारोपण से पहले यह दवा देनी चाहिए।' यह दवा इलाज की प्रक्रिया के दौरान मरीजों की सेहत को बेहतर रखने में मददगार है।

बोन मैरो कैंसर के कारण

बोन मैरो यानि अस्थि मज्जा मुख्य हड्डियों के बीच में एक मुलायम व स्पॉजी टिशू है। इसमें रक्त बनाने वाली अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं (जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है), सफेद कोशिकाएं (जो संक्रमण से लड़ती हैं) और प्लेटलेट्स(जो ब्लड क्लॉटिंग से मदद करती है) में विकसित होती हैं।

बोन मैरो कैंसर के प्रकार

बोन मैरो कैंसर दो तरह का होता है प्राइमरी और सेकंडरी। इन्हें प्राथमिक और माध्यमिक बोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता हैं। जब बोन मैरो कैंसर के सेल्स हड्डियों के बजाए अन्य भागों में मिलते हैं तो ये प्राथमिक बोन कैंसर की श्रेणी में आता है। प्राथमिक बोन कैंसर के भी कई रूप हैं जैसे- ल्यूकेमिया, लिम्फोमस और मल्टी माइलोमा। जब बोन मैरो में असामान्य रूप से सफेद कोशिकाओं का उत्पाद होने लगता हैं।

मल्टीपल माइलोमा कैंसर तब विकसित होता है जब बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स की उत्पति होने लगती हैं। लिम्फोमा आमतौर पर लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है लेकिन कुछ और स्थितियों में भी बोन मैरो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे बुखार होना, वजन का कम होना, हड्डियों में दर्द होना, बिना कारण फ्रैक्चर होना, एनीमिया, शारीरिक कमजोरी होना, शरीर में सूजन आना, ठीक से पोषण ना लेना, अत्यधिक थकान होना, चक्कर आना, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना सभी बोन मैरो कैंसर और बोन कैंसर के लक्षणों में से एक हैं।

कीमोथेरेपी

बोन मैरो कैंसर के इलाज में सबसे पहले कीमोथेरेपी प्राथमिक उपचार के लिए अपनाई जाती हैं। कीमोथेरेपी के दौरान दवाएं दी जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं। यह दवाएं खाने के लिए या फिर नसों में दी जाती है। कैंसर के इलाज के लिए आमतौर पर कुछ दवाएं मशहूर हैं जो कि डॉक्टर की सला?ह पर दी जाती हैं।

रेडिएशन थेरेपी

इस प्रक्रिया के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विकिरण चिकित्सा दी जाती है। इस थेरपी से जल्दी ही कैंसर के सेल्स? मर जाते हैं और मरीज जल्दी ही ठीक होने लगता हैं।

रेडियो इम्यून थेरेपी

इस थेरपी के माध्यम से सिर्फ ट्यूमर को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है जिससे हेल्दी सेल्स बच जाते हैं और ट्यूमर से प्रभावित सेल खत्म हो जाते हैं।

शल्य चिकित्सा

सर्जरी से कई बार बोन कैंसर का उपचार करना पड़ता है। इसके लिए यदि बोन कैंसर बहुत फैल गया है और रोगी को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। या फिर बोन कैंसर किसी जोड़ के आसपास है तो इस स्थिति में शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। कई बार जब मरीज गंभीर स्थिति में होता है तो भी सुरक्षा की दृष्टि से शल्य चिकित्सा से बोन कैंसर का ईलाज किया जाता है।

जानें कैसे होता है बोन कैंसर का उपचार

नर्म, खंखरे ऊतक जो हड्डी के केंद्र में मौजूद होते हैं उनको बोन मैरो कहा जाता है। ये टिश्यु स्टेम सेल में शामिल होते हैं और अलग-अलग रूप से रक्त में शामिल होते हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेंटलेट्स में ये ऊतक पाए जाते हैं। बोन मैरो कैंसर तब होता है जब मैंलीगेंट सेल्सो यानी घातक कोशिकाएं रक्त में वि?कसित होनी शुरू हो जाती हैं। सभी बोन मैरो कैंसर से पीड़ित मरीजों के पास एक ही प्रश्न होता है कि क्या बोन मैरो कैंसर का इलाज संभव है। क्या बोन मैरो कैंसर का ईलाज संभव है तो आइए जानें कुछ बातों को।

सिंगापुर के समलैंगिक व्यक्ति को सरोगेट बेटे को गोद लेने का अधिकार मिला

सिंगापुर (एजेंसी)।

रुढिवादी सिंगापुर में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सोमवार को एक समलैंगिक व्यक्ति को अमेरिका में सरोगेसी (किराये की कोख) के जरिये जन्मे अपने बच्चे को गोद लेने को मंजूरी प्रदान की. सिंगापुर धनी राष्ट्र है और कई मायने में आधुनिक है लेकिन वहां समलैंगिकता की आलोचना होती है.

यहां समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं है और कानून के तहत दो पुरुषों के बीच यौन संबंध अवैध है. यह कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से है लेकिन कभी-कभार ही यह कानून लागू किया जाता है.

वर्तमान मामले में उक्त व्यक्ति, जिसके लंबे समय से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध थे, ने पहले सिंगापुर में गोद लेने के बारे में जानकारी हासिल की लेकिन उसे बताया गया कि समलैंगिक दंपति को ऐसी अनुमति मिलने की संभावना नहीं है.उसने अमेरिका में एक सरोगेट मां की तलाश की जिसने दो लाख डॉलर में उसके बच्चे को जन्म देने पर सहमति जताई.

सिंगापुर में सरोगेसी पर प्रतिबंध है. उसके बेटे का जन्म हुआ और अब वह पांच वर्ष का है. 46 वर्षीय व्यक्ति अपने बेटे को सिंगापुर लेकर आया और उसे गोद लेने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन दिया ताकि उसे सिंगापुर की नागरिकता हासिल हो सके. पिछले वर्ष दिसम्बर में जिला न्यायाधीश ने शुरुआती आवेदन खारिज कर दिया. लेकिन उसने सिंगापुर के उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जहां फैसला उसके पक्ष में आया.

मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने फैसला देते हुए कहा कि ''यह साक्ष्य हमें दिखाता है कि बच्चे के हित में गोद लेने का आदेश दिया जाए.''

सेंट्रल जोन द्वारा चलाया गया मेगा अतिक्रमण अभियान

कादरशा नाल रोड से अतिक्रमण हटा खाली कराई गई जगह

सूरत। सोमवार की सुबह से ही सेंट्रल जोन द्वारा पुलिस बंदोबस्त के साथ कादरशानाल इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान रोड़ के किनारे रखे फर्नीचर तथा टायर ट्यूब जप्त कर लिया गया।

प्राप्त जानकारी अनुसार सोमवार को सेंट्रल जोन की टीम ने सिक्युरिटी स्टाफ तथा पुलिस बंदोबस्त के साथ रोड़ पर अतिक्रमण कर ट्राफिक जाम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिसमें कादरशा नाल से एकता सर्कल तक रास्ते के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया गया। यहां अतिक्रमण के कारण अक्सर ट्राफिक जाम की समस्या से वाहन चालको को दो चार होना पड़ता था। इस क्षेत्र में ज्यादातर भंगार की दुकाने है जिन्हें मुस्लिम समाज के लोग द्वारा चलाया जाता है। जिसमें टायर ट्यूब से लेकर ए.सी, फ्रीज तथा भंगार के भाव मिलते है। पुराने फर्नीचरों की भी यहां दुकाने है जो सड़को के किनारें लगाकर चलाई जाती है। जिससे यहां अक्सर ट्राफिक जाम रहता है। सेंट्रल जोन द्वारा इस तरह का अतिक्रमण हटाओं अभियान पहले भी चलाया गया है लेकिन पहले भी दुकानदार कुछ ही दिनों के बाद रोड़ पर अपना सामान रखने लगते है और ट्राफिक समस्या को बढावा देते है। देखना होगा की सेंट्रल जोन के अधिकारी इस समस्या का स्थाई समाधान निकाल पाते है या नहीं ?

कारखाने की लिफ्ट में फंसकर कारीगर की मौत

सूरत। कडोदरा के अक कारखाने की लिफ्ट में गिर जाने से कारीगर की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी अनुसार मूल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ का रहने वाला गुलाब सिंह हाल में कडोदरा के निकट बरेली गांव में रहकर हरिपुरा गांव स्थित विधाता इंडस्ट्रीज के लुम्स कारखाने में काम करता था। 18 साल की उम्र के इस युवक की रविवार की रात 12.30 बजे के करीब कामकरते वक्त लुम्स खाता के लिफ्ट से गिरकर मौत हो गई। ऊंचाई से गिरने पर युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संदर्भ में कडोदरा पुलिस ने दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज कर लिया है। विदित हो कि सूरत शहर में ऐसे हजारों कारखाने है जहां सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सरकार के श्रमकानून के अनुसार जोखिम वाले काम में 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं रखा जा सकता। परन्तु इन कारखाना संचालकों द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जिया उड़ाई जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप रोज दुर्घटनाएं होती है।

पांडेसरा में गैस लीक होने से लगी आग पिता पुत्र झुलसे

सूरत। सोमवार की सुबह 5 बजे के करीब पांडेसरा के अपेक्षा नगर में गैस सिलिंडर लीकर होने से आग लग गई। जिससे पतरे का छत टूटकर गिर गया। आग की चपेट में आकर घर पर विस्तर जल गया। घर में सो रहे पिता-पुत्र झुलस गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उज्जनाथ शाह तथा उनका पुत्र टीकू शाह इस आग में झुलस गए जिन्हें उपचार के लिए न्यू सिविल हास्पीटल में दाखिल कराया गया है । जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

भारतीय सेना में आहिर रेजीमेंट बनाने के लिए लिखा प्रधानमंत्र को पत्र

सूरत। भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट बनाने की मांग से कई मुद्दों को लेकर आहिर समाज के अग्रणी अमृत आहिर ने समाज के अग्रणियों के साथ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। इस आवेदन पत्र में आहिर समाज के वीर पुरुषों की गाथा को स्कूलों के पाठयक्रमों में शामिल करने का निवेदन किया गया। आहिर समाज द्वारा समाज के कल्याम के लिए चालाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार केयोगदान की मांग की।

दक्षिण गुजरात में शीतलहर का असर

वलसाड़ में 12 तथा नवसारी में 13 डीग्री तापमान

सूरत। समग्र दक्षिण गुजरात में पिछले तीन दिनों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर दिशा की और से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण राज्य में शीतलहर चल रही है। तापमान में ज्यादा गिरावट न होने के बावजूद तेज हवाओं के कारण ठिठुरन की स्थिति पैदा हो गई है। सूरत मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.3 डीग्री तथा न्यूनतम तापमान 15.8 डीग्री दर्ज किया गाय। हवा में नमी की मात्रा 55 प्रतिशत तथा हवा का दबाव 1117.6 मिलाबार दर्ज किया गया। शहर में सुबह से ही 6 किमी प्रतिघटें की रफ्तार से हवाए चली नवसारी मौसम विभाग के अनुसार नवसारी का न्यूनतम तापमान 13 डीग्री दर्ज किया गया। वलसाड़ मौसम विभाग के अनुसार वलसाड़ का न्यूनतम तापमान 12 डीग्री तथा अधिकतम तापमान 31.4 डीग्री दर्ज किया गया। सम्पूर्ण दक्षिण गुजरात में उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। जिसके चलते गर्म कपड़ों में लोग नजर आए।

वराछा, कापोद्रा में ट्रफिक पुलिस द्वारा

वाहनों को डीटेन कनरे पर पथ्थर बाजी

सूरत। ट्रफिक नियमों का उल्घंन करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाना पुलिस के लिए जोखिम बन गया है। क्रेन द्वारा वाहनों को उठाकर ले जाना भारी पड़ रहा है। खासकर वराछा तथा कापोद्रा में स्थिति भयावह बन गई है। वराछा के वरोड़ा प्रिस्टेज के निकट लोगों के समूह ने क्रेन द्वारा वाहनों के ले जाए जाने पर हमला कर दिया गया। लोगों ने पथ्थरबाजी कर क्रेन चालक को घायल कर जबरदस्ती क्रेन से अपने वाहनों को उतार लिया। इस भीड़ में एक व्यक्ति तो अपने को डी.वाय.एस.पी तक बता रहा था। इस व्यक्ति ने हेड कांस्टेबल अनिल भाई बाल्मीक भाई की गाड़ी नं. जी जे 5, के जे 9532 के चालक ने अज्ञातों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दिए शिकायत के अनुसार वरोड़ प्रिस्टेज के सामने उर्वि सोसायटी के पास ट्राफिक विभाग के क्रेन के आदमी ट्राफिक नियम के विरुद्ध जाने वालों पर कार्रवाई कर रहे थे। तभी 5 लोगों ने आकर क्रेन से गाड़ी उतारनी शुरु कर दी तथा उसपर कार्यरत कर्मचारियों पर हमला कर दिया तथा पथ्थरबाजी कर क्रेन की तोड़ फोड़ कर 1500 रुपये से अधिक का नुकसान कर दिया। कापोद्रा पुलिस ने सी.सी.टी.वी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

आदिवासी कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में लोक दरबार ओायजित

चार एकड़ से अधिक जमीन पर मिलेगा नया विद्युत कनेक्शनः गणपतभाई वसावा

सूरत। ग्राहकों की विद्युत समस्या के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित दक्षिण गुजारत विद्युत कम्पनी द्वारा सोमवार को उमरपाड़ा तथा मांगरोल में लोक दरबार आयोजित किया गया। जिसकी सम्पूर्ण कार्रवाई आदिवासी कल्याणमंत्री गणपतभाई वसावा की अध्यक्षता में की गई। इस लोक दरबार में 49 प्रश्न रखे गए थे जिसमें से 30 प्रश्नों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। इस अवसर पर गणपतभाई वसावा ने कहा कि विद्युत समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण के लिए राज्यभर में लोक दरबार का आयोजन किया जा रहा है।

श्रेष्ठ कार्य के लिए द.गु.वि.क. को मिला पुरस्कार

सूरत। दक्षिण गुजरात विद्युत कम्पनी को गत 14 दिसंबर को ऊजा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्यम में केंद्र सराकर के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नेशनल एनर्जी कन्जवैशन अवार्ड-2018 के तरह श्रेष्ठ कामकाज के लिए पुरस्कृत किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक खास कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के हाथों यह पुरस्कार कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर्द्रा अग्रवाल को दिया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अरा.के.सिंह ऊर्जा मंत्रालय सचिव ए.के. भल्ला सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। यह पुरस्कार दक्षिण गुजरात विद्युत कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे ऊर्जा बचाओं अभियान तथा विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए दिया गया। कम्पनी को पुरस्कृत किए जाने से कम्पनी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला।

सूरत। सूरत में आयोजित उडीसा महोत्सव कार्यक्रम में पधारे उडीसा के मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही लगा गो बैंक का बैनर प्रवासी उडिया चिटफंड जमाकारी महासंघ की तरफ से यह बैनर पांडेसरा क्षेत्र में लगाया गया था।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)